चिन्ताएं ही चिन्ताएं

डॉ. रामवीर

चिन्ताएं बहुत तरह की होती हैं। छोटी चिन्ता बडी चिन्ता। छोटी चिन्ता का एक बडा उदाहरण है

'फीलिंग मंडेइश'। छह दिन नौ से पांच की चक्की में पिसने के बाद संडे आता है, बडा अच्छा लगता है। उस दिन देर तक सोते हैं। घर में गप शप में समय बीतता है, पर दोपहर बीतते बीतते जब तक शाम की चाय का समय होता है चिन्ता होनी शुरु हो जाती है ओह यार कल तो मंडे है। इस मन:स्थिति के लिए इंगलिश में मुहावरा बन गया फीलिंग मंडेइश। इंगलिश इस माने में समर्थ और उदार भाषा है कि आवश्यकता होने पर नया शब्द घडने और घडा न जा सके तो उधार लेने में संकोच नहीं करती। हिन्दी में नए शब्दों को भाषा शुद्धतावादियों की रैगिंग झेलनी पडती है और उधार लेने के बारे में उस की मान्यता 'नैवर लैंड एंड नैवर बोरो' वाली है। विवशता में उधार ले भी ले तो असमर्थ भाषा समझ लिए जाने की चिन्ता में पड जाती है।

यह तो हुई छोटी चिन्ता की बात, बडी चिन्ता वह होती है जो छोटे लोग बड़े लोगों की किया करते हैं। मेरा एक पडोसी पिछले कई मास से बहुत चिन्तित था। उस की चिन्ता का केन्द्र था अमेरिका का चुनाव। मैंने समझाने की कोशिश की कि क्यों भई बेकार फिक्र में पड़े हो तो कहने लगा भाई साहब अगर ट्रम्प हार गया तो क्या होगा। मैंने कहा होगा क्या कुछ नहीं होगा, ट्रम्प हार गया तो बिडेन जीत जाएगा। मेरी प्रतिक्रिया पर अपनी चिन्ता और बढ़ाते हुए कहने लगा नहीं भाई साहब यह आप क्या कह रहे हैं। देखिये ट्रम्प साहब हमारे मोदी जी के मित्र हैं और वे हार गए तो? मेरी समझ में अब आया कि वे ट्रम्प के बहाने मोदी जी और मोदी जी के बहाने अपनी ही चिन्ता कर रहे थे। दर- असल मोदी जी ने जब थाली बजाने को कहा था तो इन सज्जन ने परात बजाई थी। मोदी जी के इतने आज्ञाकारी व्यक्ति को मोदीमित्र ट्रम्प के हारने की बड़ी चिन्ता तो होनी ही थी।

छोटी चिन्ता, बड़ी चिन्ता और तीसरी चिन्ता होती है बेमतलब की चिन्ता। इस लेखक को यह बेमतलब की चिन्ता प्राय: परेशान करती है। अब देखिये ना जब से मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरु की है मैं चिन्तित हूं यह जानने के लिए कि आखिर वे दाढ़ी क्यों बढा रहे हैं। छात्रावस्था में जो पढ़ाया गया था कि बिना कारण कोई काम नहीं होता उसे मैं अभी तक नहीं भुला पाया जब कि मेरे कई मित्रों ने विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र पढाते हुए भी इस सामान्य से सिद्धान्त को भुला रक्खा है। मेरी चिन्ता निराधार नहीं है। मैं देख रहा हूं कि ज्यों ज्यों मोदी जी की दाढी बड़ी हो रही है वे और बड़े बड़े निर्णय लेने लगे हैं। तो क्या दाढ़ी और निर्णय लेने की गति में कोई सम्बन्ध है ?

दाढीवान् प्रधानमन्त्री ने जिस तीव्रता से किसानों का हित करने की ठानी है उसी तीव्रता से किसानों की परेशानी बढी है। दाढी और राजनीति में कोई न कोई सम्बन्ध तो है, यूं ही बेबात तो कोई बात नहीं होती। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि दाढी का सम्बन्ध बंगाल के चुनाव से भी है। बंगाल की चुनावी रैलियों में स्वयं को रवीन्द्रनाथ टैगोर की छवि में दिखाने के लिए यह दाढी बढाई जा रही है। यदि ऐसा है तो प्रधानमन्त्री नाहक रिस्क ले रहे हैं, बंगाल के लोग काफी प्रबुद्ध हैं और वे टैगोर और आशाराम की दाढी का अन्तर समझ सकते हैं ।

दाढी में कोई बुराई नहीं है, पर समय और परिस्थिति से आशंका होती है। आम तौर से साठोत्तर की पकी उमर में लोग अपने चेहरे मोहरे और वेश में कोई बडा परिवर्तन नहीं करते। कभी मूंछ रख लीं कभी क्लीन शेव्ड हो गए जैसे प्रयोग युवक करते रहते हैं, पर उम्र बढने के साथ साथ च्वाइस में स्थिरता आ जाती है। तो क्या यह समझा जाए कि प्रधानमन्त्री अस्थिरमति हैं, हो भी सकता है नहीं भी। मेरी चिन्ता यह है कि मूंछ का सवाल बनने से ही समस्या गम्भीर हो जाती है, अगर दाढी का सवाल बन गया तो गम्भीरतर न बन जाए, खास तौर से तब जब दिल्ली की सीमाओं पर लाखों दाढियां प्रधानमन्त्री की दाढी की ओर देख रही हैं।

आजकल बडे चैनल्स बडी खबरें नहीं दिखाते, यह जिम्मेदारी छोटे चैनल्स को उठानी पड रही है। मेरा यह चिन्तापूर्ण लेख भी था तो बडी पत्रिका के लिए, लेकिन आजकल बडी पत्रिकाओं को देशहित के बजाए अपनी चिन्ता ज्यादा है कि कैसे वे अपने को सरकार की गुड बुक्स में लाएं, आखिर 'भारत' सरकार माता ही तो विज्ञापनदाता है। बडी पत्रिकाओं के सम्पादक आजकल उस दौर में चल रहे हैं जिस के बारे में अकबर इलाहाबादी ने कभी कहा था

कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ।

खोरी गांव में शराब माफिया सक्रिय...हर काम खुलेआम

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

सूरजकुंड पुलिस थाने में आता है यह इलाका

फरीदाबाद: सराय ख्वाजा के पास खोरी गांव में खुलेआम अवैध शराब और मादक द्रव्य बेचे जा रहे हैं। यह इलाका सूरजकुंड पुलिस थाने के तहत आता है। इस सिलसिले में जिस शराब माफिया का जिक्र आ रहा है, वो यहां रंगदारी भी वसूलता है और सरकारी जमीन पर कब्जे करता है। पिछले दिनों यहां अवैध कब्जा हटाने के नाम पर जिस तरह बड़े पैमाने पर एमसीएफ और अन्य एजेंसियों ने तोड़फोड़ की थी, उस समय भी जमीन पर अवैध कब्जा करके उसे बेचने वालों के नाम सामने आये थे। लेकिन पुलिस सहित किसी भी एजेंसी ने कार्रवाई नहीं की। उस घटनाक्रम के बाद इस तरह के धंधों में लिप्त लोगों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं।

खोरी गांव में आमतौर पर यूपी-बिहार से आया मजदूर तबका रहता है। जिसे यहां सस्ते किराये पर कमरे मिल जाते हैं। कुछ ने ऐसे ही माफिया से छोटी-मोटी जमीन खरीदकर मकान भी बना लिए हैं। शराब माफिया लोकल होने का हवाला देकर बाहर से आकर बसे लोगों पर रोब गांठता है। यहां रह रहे लोगों ने शिकायत की है कि शराब माफिया के एजेंट लोगों को पहले मुफ्त देसी शराब पिलाकर या ड्रग्स देकर आदत डालते हैं और उसके बाद उन्हीं को वही चीज बेचना शुरू कर देते हैं। हाल ही में हरियाणा के सोनीपत, पानीपत में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थीं लेकिन इसके बावजूद सूरजकुंड पुलिस की नाक के नीचे यहां इस तरह का अवैध धंधा सरेआम चल रहा है।

खोरी गांव में सक्रिय शराब माफिया का संबंध भाजपा से भी बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि शराब माफिया अक्सर फरीदाबाद के भाजपा नेताओं के नाम लेकर कहता है कि उसके उन लोगों से सीधे संबंध हैं। पुलिस उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। पुलिस का जो रवैया इस शराब माफिया को लेकर है, उसे देखकर यही लगता है कि वह सच बोल रहा है। कई भाजपा नेताओं की रैलियों में वह यहां से भीड़ भी ले जा चुका है, जिसके बदले उसे वहां से पैसे भी मिले। यही शराब माफिया खोरी गांव में फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों, रेहड़ियों से रंगदारी भी वसूल रहा है। चाहे किसी रेहड़ी वाले की बिक्री हो या न हो, शराब माफिया को पैसे देने ही पड़ते हैं।

इंद्रा कॉलोनी वालों को विधायक नरेंद्र गुप्ता, पार्षद और केंद्रीय मंत्री गूर्जर की तलाश

एक साल पहले बनी सड़क भी नहीं बची और न सीवरलाइन डली

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: शहर के वार्ड 13 स्थित इंद्रा कॉलोनी में वहां की जनता विधायक नरेंद्र गुप्ता, पार्षद सुमन भारती और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूर्जर को तलाश रहे हैं। वजह ये है कि इन लोगों ने इंद्रा कॉलोनी में एक साल पहले 19 नवम्बर 2019 में सीवरलाइन डालने के काम का शिलान्यास किया था। उस समय लगाया गया पत्थर अब कॉलोनी वालों को मुंह चिढ़ा रहा है। वहां की सड़क खुदी पड़ी है और सीवरलाइन डालने का काम ठप पड़ा है।

शिलान्यास के बाद विधायक, पार्षद और केंद्रीय मंत्री कंबल ओढ़ कर सो गए। उस समय कृष्णपाल गूर्जर ने सीवरलाइन की आधारशिला रखते हुए दावा किया था कि इस प्रोजेक्ट पर 2 लाख 18 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने उस समय नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के अफसरों को निर्देश दिया था कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए लेकिन एमसीएफ के अफसरों ने इसका उल्टा मतलब लगाया।

सितम्बर 2020 में एमसीएफ के अफसरों को याद आया कि इंद्रा कॉलोनी में तो अभी सीवरलाइन डली ही नहीं है। यह अलग बात है कि उससे पहले इस काम को करने वाले ठेकेदार से एमसीएफ के अफसरों की सेटिंग नहीं हो पा रही थी। सितम्बर में सीवरलाइन डालने के नाम पर एमसीएफ ने अपनी ही बनाई सीमेन्ट वाली सड़क को खोद डाला। लेकिन सीमेन्ट की सड़क को खोदने के बाद एमसीएफ के अधिकारी और कर्मचारी वहां से गायब हो गए। मौके पर अब न तो सड़क है और न सीवरलाइन ही डाली जा सकी है।

इंद्रा कॉलोनी का यह घटनाक्रम बता रहा है कि एमसीएफ बिना प्लानिंग किस तरह काम कर रहा है। अगर यहां सीवरलाइन डालनी ही थी तो पहले सीमेन्ट वाली रोड क्यों बनाई गई और फिर उसे खोद डाला गया। अब जब कभी सीवरलाइन डालने का काम पूरा होगा तो यहां के नागरिकों को कम से कम एक साल तक सड़क फिर से बनने का इन्तजार करना होगा। इसके बाद शायद कोई और प्रोजेक्ट आ जाए और फिर से सड़क और सीवरलाइन दोनों को तोड़ दिया जाए। हालात ये हैं कि स्थानीय नागरिकों की जिन्दगी इस टूटी हुई सड़क पर से गुजरने के दौरान नरक बन जाती है।

चारों तरफ पत्थरों के टुकड़े और मिट्टी फैली हुई है। वैसे तो पूरा फरीदाबाद ही खोद डाला गया है, बार-बार कमाई के लिए चीजों को बार-बार तोड़ा जा रहा है। तीनों ही जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता इंद्रा कॉलोनी में दांव पर लग गई है।

हमारा-आपका सरोकार

शोशेबाजी में माहिर दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को एक प्रेस कन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि हरियाणा में 50त्न से 75त्न लोकल कैंडिडेट्स को नौकरी देने वाले उद्योगों/संस्थानों को सरकार की ओर से 48000 रुपये वार्षिक दिए जायेंगे। दुष्यंत ने नई 'Haryana Enterprises & EmploymentPolicy' का ऐलान करते हुए यह बात कही। दो महीना पहले दुष्यंत ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने का निर्देश दिया था। लेकिन उद्योग जगत ने उनकी इस घोषणा का समर्थन नहीं किया। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन समेत तमाम औद्योगिक संगठनों ने इसका विरोध किया। दुष्यंत ने इसके बाद विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का बिल भी पारित करा लिया। लेकिन किसी कंपनी से हरियाणा सरकार को उत्साहजनक जवाब नहीं मिला। अब प्राइवेट कंपनी मालिकों को रिझाने के लिए 48000 रुपये देने की घोषणा की गई है। हरियाणा में जिन कंपनियों का टर्नओवर लाखों में है, क्या वे सरकार से 48000 रुपये पाने के लिए उसके झांसे में आएंगे।

दुष्यंत की शोशेबाजी बढ़ती जा रही है। वो चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां देने का राज्य में विरोध हो और वे शिवसेना की तरह हरियाणा के एकछत्र नेता बन जाएं। दुष्यंत का यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन यह चिंता का विषय है कि इतना पढ़ा लिखा नेता संविधान के दायरे से बाहर जाकर हरियाणा में सिर्फ लोकल लोगों को प्राइवेट नौकरियां देने की वकालत कर रहा है। संविधान ने आजादी है कि भारतीय नागरिक किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकते हैं।

ऐसा लगता है कि दुष्यंत समेत सारे भाजपाई और जेजेपी नेता उद्योगपतियों को बेवकूफ समझते हैं। जो उद्योग बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ की सस्ती लेबर के दम पर चल रहे हों, वो लोकल लोगों को नौकरी देकर क्यों मुसीबत मोल लेना चाहेंगे। लोकल लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी देने के अपने खतरे हैं। यही वजह है कि दुष्यंत की यह घोषणा एक शोशेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जनता इन बातों से सरोकार रखे कि नेता किस तरह उन्हें हरियाणा बनाम बिहार या यूपी की लड़ाई में उलझाना चाहते हैं। दरअसल, हरियाणा के युवकों से दुष्यंत का वादा था कि सरकारी नौकरियों में राज्य के युवकों को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन पद खाली पड़े होने के बावजूद सरकारी नौकरियां हरियाणा के युवकों को मिल नहीं रही हैं। कुछ विभागों में लिखित परीक्षा तक हो चुकी है लेकिन उनके नतीजे घोषित नहीं किए जा रहे हैं। हरियाणा का युवक हमेशा सरकारी नौकरी चाहता है। लेकिन दुष्यंत उसे प्राइवेट नौकरी के लॉलीपॉप से बहलाना चाहते हैं।

मजदूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि यही दुष्यंत कल तक किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन जब किसान इस सर्दी में सड़कों पर बैठा है तो दुष्यंत दिल्ली की खान मार्केट में शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में मजदूर मोर्चा ने पिछले अंक में रिपोर्ट प्रकाशित की थी।